



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]  
No. 36]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 2001/माष 18, 1922

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2001/MAGHA 18, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001

सं. 54-(आर ई-00)/1997—2002

फा. सं. 01/94/180/163/ए एम 00/पी सी-4.—का.आ. सं. 283(अ) दिनांक 31-3-97 के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में यथाअधिसूचित निर्यात-आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (आर ई-00), 1997—2002 में निम्नलिखित संशोधन कराये हैं—

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आए भूकम्प से निर्यात-इकाईयों सहित बहुत सी इकाईयां ध्वस्त हो गई हैं। गुजरात राज्य में भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित इकाईयों के सम्बंध में, जहां-जहां अपेक्षित हों, निम्नलिखित संशोधन किए गये हैं मान लिया जाएगा:

- इ पी सी जी योजना के अधीन भूकम्प से प्रभावित इकाईयों को पैराग्राफ 6.11 के तहत वर्षावार निर्यात दायित्व के वर्षावार/वर्षावार के ब्लाक को पूरा करने अथवा पूर्ण निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए एक वर्ष को आम विस्तार उपलब्ध होगा।

2. भूकम्प से क्षतिग्रस्त गुजरात की निर्यातीन्मुख इकाईयों और कान्डला में विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों के संबंध में निर्यात निष्पादन की मानिटरिंग को 30-6-2001 तक स्थगित कर दिया जाएगा।
3. अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के अधीन पैराग्राफ 7.22 के तहत निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए एक वर्ष का और समय दिया जाएगा।
4. ऐसे सभी अग्रिम लाइसेंस जो भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित पत्तन कार्यालयों के साथ पंजीकृत हैं और जिनकी वैधता अवधि जनवरी 2001 या इसके बाद समाप्त हो रही है उनकी वैधता अवधि पैराग्राफ 7.23 के अधीन एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई मान लिया जाएगा।
5. इसी प्रकार, गुजरात में भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में पंजीकरण के पत्तन के साथ डी ई पी बी और डी एफ आर सी की वैधता डी ई पी बी/डी एफ आर सी के मामले में एक साल के लिए बढ़ाई हुई मानी जाएगी जो मास जनवरी, 2001 में या उसके पश्चात समाप्त हो गई हो।
6. जहाँ कहीं भी निर्धारित दस्तावेजों में मौलिक दस्तावेजों को जमा करवाना शामिल हों वहाँ गुजरात में भूकम्प से प्रभावित यूनिटें किसी लाइसेंस के दावे हेतु और निर्यात दायित्व के अनुपालन हेतु बैंक/सीमा शुल्क प्राधिकारियों जैसा भी मामला हो, द्वारा विधिवत सत्यापित दस्तावेजों की डुप्लीकेट प्रतियाँ जमा करवा सकती है। कोई भी कटौती, जोकि साधारणतया आवेदक द्वारा डुप्लीकेट दस्तावेज जमा करवाने पर लागू होती है, ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी।
7. जहाँ कहीं भी आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा (विशेष आयात लाइसेंस के दावे हेतु आवेदन को छोड़ कर) मास जनवरी, 2001 में या उसके पश्चात आती है, वह 31 दिसम्बर, 2001 तक या लागू सामान्य समय सीमा जो भी बाद में हो, तक बढ़ा दी जाएगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 7th February, 2001

**No. 54 (RE-00)/1997—2002**

**F. No. 01/94/180/163/AM 00/PC-IV.**—In exercise of powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997—2002, as notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. No. 283(E) dated 31-3-97, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures (Vol. 1) (RE-00), 1997—2002.

The earthquake which struck Gujarat on 26<sup>th</sup> January, 2001 had devastated many units including exporting units. The following amendments shall be deemed to have been made wherever required in respect of the units located in the areas affected by earthquake in the State of Gujarat.

1. Under paragraph 6.11, one year general extension in export obligation both for fulfilling the yearwise/block of yearwise export obligation or for fulfilling the complete export obligation shall be available to units hit by earthquake under the EPCC Scheme.
2. The monitoring of export performance in respect of EOU in Gujarat and units in Kandla Special Economic Zone damaged by earthquake shall be deferred till 30.6.2001.
3. Under paragraph 7.22, a further period of one year shall be given for completing the export obligation under Advance Licensing Scheme.
4. Under paragraph 7.23 relating to validity of Advance Licence one year deemed validity shall be extended to all Advance Licence with port of registration in areas affected by earthquake which have expired in the month of January, 2001 or thereafter.
5. Similarly, the validity of DEPB and DFRC with port of registration in areas affected by earthquake in Gujarat shall be deemed to have been extended by one year in respect of DEPB/DFRC which have expired in the month of January, 2001 or thereafter.
6. Wherever the prescribed documents includes the submission of original documents, the units affected by the earthquake in Gujarat may submit duplicate copies of the document duly attested by the Bank/Customs authorities, as the case may be, for claiming any licence and also for discharge of export obligation. No cut, which is normally applicable when an applicant submits the duplicate documents, shall be applicable in such cases.

7. Wherever the time limit for filing an application (except an application for claiming Special Import Licence) falls in the month of January, 2001, or thereafter, the same shall be extended to 31<sup>st</sup> December, 2001 or the normal time limit applicable whichever is later.

**This Issues In public Interest.**

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade